मुख्यमंत्री ने मुडिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की

उन्होंने सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं को जल सेवा व प्रसादी वितरण किया

डीग/ भरतपुर, 9 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपत्नीक दर्शन कर पूजा-अर्चना की।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने बताया कि वे गत 25 वर्ष से अधिक समय से मुडिया पूर्णिमा के अवसर पर गिर्राज जी आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुडिया पूर्णिमा के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में प्याऊ पर श्रद्धालुओं को पानी पिलाया।

शर्मा ने इससे पहले सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की। सीएम ने पूंछरी में प्याऊ पर जल सेवा भी की तथा भक्तों को भंडारे की प्रसादी का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने विश्राम स्थली की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रतिवर्ष मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी में श्रद्धालुओं को शीतल जल एवं प्रसादी का वितरण करते हैं।

मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो उसे अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है।

उन्होंने कहा कि वे गत 25 वर्षों से अधिक समय से मुड़िया पूर्णिमा के अवसर पर गिर्राज जी आ रहे हैं, यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. शैलेश सिंह आदि उपस्थित थे।

ट्रंप ने 200 व्यापारिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहुंच देने की पेशकश कर चुके हैं।

लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार वार्ताकारों के लिए यह ही पर्याप्त नहीं है। वे क्या चाहते हैं, यह शायद उन्हें खुद भी स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार दोहराया है कि दुनिया के देशों ने दशकों तक अमेरिका को "लूटा" है। अमेरिकी रुख को समझाते हुए उन्होंने कहा।

"वे कहते हैं... "हम तुम्हें पूरा एक्सेस देंगे, और तुमसे कोई टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन कृपया हम पर भी टैरिफ मत लगाना," और हमें यह सौदा पसंद नहीं आता, ट्रंप ने कहा। हम सख्त नहीं हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि अमेरिका उन देशों से पैसा वसूले, जो हमें वर्षों से लूटते आए हैं, और हमारी पीठ पीछे हमें मूर्ख समझकर हँसते रहे हैं।

इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अब उन देशों से शुल्क या लाभ वसूलना चाहता है, जो उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं। क्या वह चीन से यह अपेक्षा करता है कि वह अमेरिकी व्यापार घाटे से कमाए गए विदेशी मुद्रा भंडार को वापस लौटाए?

वैसे भी, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कई मंचों पर कहा है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता "बहुत पेशेवर ढंग से" चल रही है। किसी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में समय लगता है, क्योंकि इसमें अलग-अलग वस्तुओं और क्षेत्रों के लिए विस्तृत मानकों पर सहमति बनानी होती है।

अमेरिकी वाणिज्य विभाग में ऐसे विशेषज्ञों की बहुत बड़ी संख्या है, संभवत: किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में देशों और उत्पाद श्रेणियों के लिए इतने व्यापक व्यापार समझौते बनाना और उन्हें एक ही समय पर लागू करना वास्तव में अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है।

वायु सेना का जैगुआर फाइटर प्लेन राजलदेसर के पास क्रैश हुआ

सूरतगढ़ से रवाना हुए विमान के दोनों पायलट दुर्घटना में शहीद हुए

चूरू/राजलदेसर, 9 जुलाई (निसं)। राजलदेसर कस्बे की निकटवर्ती ग्राम पंचायत भानुदा में भारतीय वायु सेना का जैगुआर फायटर जैट क्रैश हो गया, घटना में दो पायलट शहीद हो गए।

- एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, फाइटर प्लेन उसके खेत के ऊपर से गुजरा था, तब उसमें आग लग चुकी थी। पायलट गाँव को बचाते हुए प्लेन को आबादी से दूर ले गया।

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बताया कि दोनों पायलट ट्रेनिंग पर थे और सूरतगढ़ से रवाना हुए थे। गांव के ही राजदीप भुवाल तथा इंद्राज प्रजापत ने बताया कि यह फाइटर प्लेन उनके खेत के ऊपर से गुजरा था। उस समय उसमें आग लग चुकी थी, लेकिन गांव को बचाने के चक्कर में पायलट ने प्लेन को गांव के बाहर उतारने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से लग चुकी थी एवं एक पेड़ से टकराने के बाद प्लेन पूरी तरह जल कर नष्ट हो गया। गांव वालों ने घटना की सूचना राजलदेसर पुलिस थाना को दी, पुलिस थाना ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया तथा मौके पर गांव के ही नहीं, अपितु आसपास के हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। घटना के बाद बीकानेर पुलिस महानिदेशक ओमप्रकाश मीणा, बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, चुरु पुलिस अधीक्षक जय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुजानगढ़, दिनेश कुमार सहित, अनेक अधिकारी मौके पर पहुँचे।

घटना की सूचना मिलते ही वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर घटना स्थल पर पहुँचा। सेना के अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं दोनों पायलटों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। समाचार लिखे जाने तक पायलटों के नामों की पुष्टि नहीं हुई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा, यह हादसा बहुत दुखद है। बीकानेर पुलिस के आईजी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि पायलटों के नाम की जानकारी इंडियन एयर फोर्स के उच्च अधिकारियों के आने के बाद ही उपलब्ध करवाई जायेगी। इस घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र सिंह राठौड़ आदि ने इस दुखद घटना पर शोक प्रकट किया।

ट्रंप की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और खासकर भारत, जो एक नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और बहुध्रुवीयता का समर्थन करने का मुखर पक्षधर है। दूसरी ओर, अमेरिका उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक प्रमुख रक्षा सहयोगी और प्रौद्योगिकी निवेशक है।

भारत के लिए खतरा ट्रंप के लेबल की अस्पष्टता में है, उनकी नजर में "एंटी-अमेरिकी" व्यवहार क्या है? क्या रूस से कच्चे तेल का निरंतर आयात भारत के लिए दंड का कारण बन सकता है? या फिर ईरान के साथ बढ़ता व्यापार, जो अब ब्रिक्स का सदस्य है? या फिर भारत द्वारा "नॉन डॉलर" वैश्विक भुगतान प्रणाली के लिए भारत की वकालत?

चीन, जिसका अमेरिका से टकराव स्पष्ट है, के विपरीत, भारत सूक्ष्म दृष्टिकोण पसंद करता है। लेकिन ट्रंप के आर्थिक राष्ट्रवाद में सूक्ष्मता के लिए बहुत कम जगह है। अगर भारत को मॉस्को या तेहरान के करीब देखा जाता है, तो वॉशिंगटन पलटवार कर सकता है। भारतीय वस्त्र, फार्मा, और सॉफ़्टवेयर जैसे क्षेत्रों पर 10 प्रतिशत शुल्क व्यापार-आधारित क्षेत्रों को गहराई तक प्रभावित कर सकता है और वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकता है।

तनाव को बढ़ाते हुए, मलेशिया के व्यापार मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि जबकि वह ब्रिक्स के सिद्धांतों का समर्थन करता है, लेकिन अमेरिका "मलेशिया का एक प्रमुख आर्थिक साझीदार बना हुआ है।" सऊदी अरब और वियतनाम, जो सम्मेलन में उपस्थित थे, ने चुप्पी साध ली और ट्रंप से टकराने का कोई इरादा नहीं जताया।

ब्रिक्स के अंतिम संवाद में कूटनीतिक रूप से शुल्क और सैन्य आक्रमण के बारे में चिंता जताई गई, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया। यह एक सावधानी से तैयार की गई ढाल थी, तलवार नहीं। और इस तरह से सम्मेलन एकजुट प्रतिबद्धता में नहीं, बल्कि रणनीतिक चुप्पी में समाप्त हो गया।

भारत के लिए संदेश स्पष्ट है, ब्रिक्स का प्रयोग अब और साहसी होता जा रहा है, लेकिन लेन-देन के पक्षधर अमेरिकी राष्ट्रपति के तहत बहुपक्षीय महत्वाकांक्षा की कीमत महंगी हो सकती है। भारत की स्थिति तलवार की धार पर चलने जैसी है, ब्रिक्स के साथ भी संबंध रखना है और ट्रंप के अगले टैरिफ हमले का निशाना भी नहीं बनना है।

11 जुलाई को तय समय पर देश भर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित होगा। आरोपी जावेद के वकील ने कहा, "यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज़ हो रही है। ट्रेलर 4 जुलाई को रिलीज़ हुआ था। इसमें सिर्फ अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष का दृष्टिकोण दिखाया जा रहा है।"

याचिका की अर्जेंट सुनवाई की माँग को अस्वीकार करते हुये पीठ ने कहा, "(याचिका को) कोर्ट के पुन: खुलने पर संबंधित पीठ के समक्ष प्रस्तुत करें। फिल्म रिलीज़ होने दें।"

ज्ञातव्य है कि राजस्थान के उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के दो लोगों द्वारा कन्हैयालाल की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा भी किया था।

कन्हैयालाल की हत्या इसलिये की गई थी कि उसने कथित रुप से भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थी। ज्ञातव्य है कि नूपुर शर्मा ने पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपी गई और इस घटना के सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी संख्या 8 द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मामले की निष्पक्ष सुनवाई में हस्तक्षेप कर सकती है।

याचिका में कहा गया है, "फिल्म का ट्रेलर और प्रचार सामग्री भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री से युक्त है, जिससे देश की धार्मिक एकता को खतरा हो सकता है और यह इस समय चल रही न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है।" क्योंकि यह प्रकरण इस समय विशेष एनआईए अदालत में विचाराधीन है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि आरोपी पर अभी दोषसिद्ध नहीं हुए हैं, और इस तरह का ट्रेलर और फिल्म, जो आरोपियों को दोषी के रुप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं। याचिका में कहा गया है, "ऐसे समय पर इस तरह का ट्रेलर जारी करना, जिसमें आरोपियों को दोषी और कहानी को सच्चाई के रूप में दिखाया गया है, न्यायिक प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह निर्दोषता की धारणा को कमज़ोर करता है और जनमत को प्रभावित कर सकता है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ सकता है, जबकि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।"

याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने और सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा जारी सैंसर सर्टीफिकेट को रद्द करने की मांग की गई है।

'हम बिहार के लोगों का वोट चोरी नहीं होने देंगे'

इंडिया गठबंधन के बिहार चक्काजाम में शामिल होने आए राहुल गांधी ने कहा

पटना, 9 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केन्द्र की एन.डी.ए. मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के पक्ष में धांधली की गई थी और अब मोदी सरकार इसी मॉडल को बिहार चुनाव में अपनाना चाहती है।

इंडिया गठबंधन के चक्का जाम में शामिल होने आए राहुल गाँधी ने कहा कि गरीबों के हक को छीनने की साजिश रची जा रही है। लेकिन हमलोग ऐसा नहीं करने देंगे।

राहुल कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीतकर आया, जबकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बुरी तरह हार गया। उस समय हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस गंभीर विषय पर काम शुरू किया। हमने जांच की तो पता चला कि लोकसभा से ज्यादा मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव में मतदान किया। आश्चर्यजनक ढंग से एक करोड़ वोट बढ़ गए। एक दिन में चार से पांच हजार वोट रजिस्टर हुए। जब हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, तब चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं कहा। हमने चुनाव आयोग से कहा कि कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। यही खेल वे बिहार में भी करना चाहते हैं।

- राहुल ने कहा सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला था पर हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी भाजपा और आरएसएस के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। पहले चुनाव आयुक्त को सभी पार्टियां और चीफ जस्टिस मिलकर चुनते थे, लेकिन अब केवल भाजपा ही चुनाव आयुक्त को चुनती है। यही सच्चाई है। बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपका वोट ही नहीं, भविष्य भी चोरी किया जा रहा है। लेकिन, इंडिया गठबंधन आप सबके साथ खड़ा है। हम लोग वोट की चोरी नहीं होने देंगे।

बिहार में दिखा महागठबंधन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(ईसीआई) के खिलाफ नारे लगाए और बैनर लहराए।

दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और टायर जलाकर सडकों को जाम किया। वैशाली में मुजफ्फरपुर-हाजीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच22) को, भैसें खड़ी करके, अवरुद्ध किया गया। नवादा में, इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने झारखंड सीमा के पास राजौली में एनएच20 पर यातायात बाधित किया। विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में राजद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीवान के जेपी चौक को बंद कर दिया। इस दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल-कॉलेज और वित्तीय संस्थान बंद रहे।

जहानाबाद, आरा, अररिया, सुपौल, सहरसा, कटिहार और किशनगंज से भी प्रदर्शन की खबरें मिलीं, जहां महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

कानून-व्यवस्था के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) पंकज दराड़ ने कहा कि बंद के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए तथा "कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई।"

विपक्षी दलों ने चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण की घोषणा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी। पिछले एक दशक में, ईसीआई ने आधार और राशन कार्ड को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन इस बार पुनरीक्षण के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के दस्तावेजों की आवश्यकता बताई गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे दस्तावेजों की अनुपलब्धता, विशेष रूप से पिछड़े समुदायों के लोगों को, उनके वोट के अधिकार से वंचित कर सकती है।24 जून को चुनाव आयोग ने इस पुनरीक्षण की घोषणा करते हुए कहा था कि मतदाता सूची को साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि शहरीकरण, बार-बार पलायन, पहली बार वोट डालने वालों की बढ़ती संख्या, मृत्यु की रिपोर्टिंग की कमी और अनिर्दिष्ट विदेशी नागरिकों के नामों के शामिल होने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आयोग ने बताया कि बिहार में अंतिम बार मतदाता सूची पुनरीक्षण 2003 में हुआ था, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों को कवर किया गया था। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता सूची में रखा जाए। इसके लिए उसने चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2003 की सूची को पात्रता का प्राथमिक प्रमाण माना जाए, जब तक कि इसके विपरीत कोई सूचना प्राप्त न हो।

सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें इस पुनरीक्षण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया की समय सीमा और तरीके, जिसमें नागरिकता सिद्ध करने के लिए 11 दस्तावेज मांगे गए हैं (जिनमें आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे आम दस्तावेज शामिल नहीं हैं) को लेकर चिंता जताई है।

हाई कोर्ट ने पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिफारिश उच्च स्तर पर भेजी। प्राधिकृत अधिकारी ने मामले में विस्तृत जांच करानी चाही, लेकिन इस दौरान ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की गुहार की गई। महाधिवक्ता ने कहा कि जब कोई निर्णय ही नहीं किया गया तो केवल निर्णय की प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती कैसे दी जा सकती है। इसलिए याचिका को खारिज किया जाए। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने कहा कि तीनों सिफारिश निर्णय न होकर निर्णय लेने की प्रक्रिया का भाग थी।

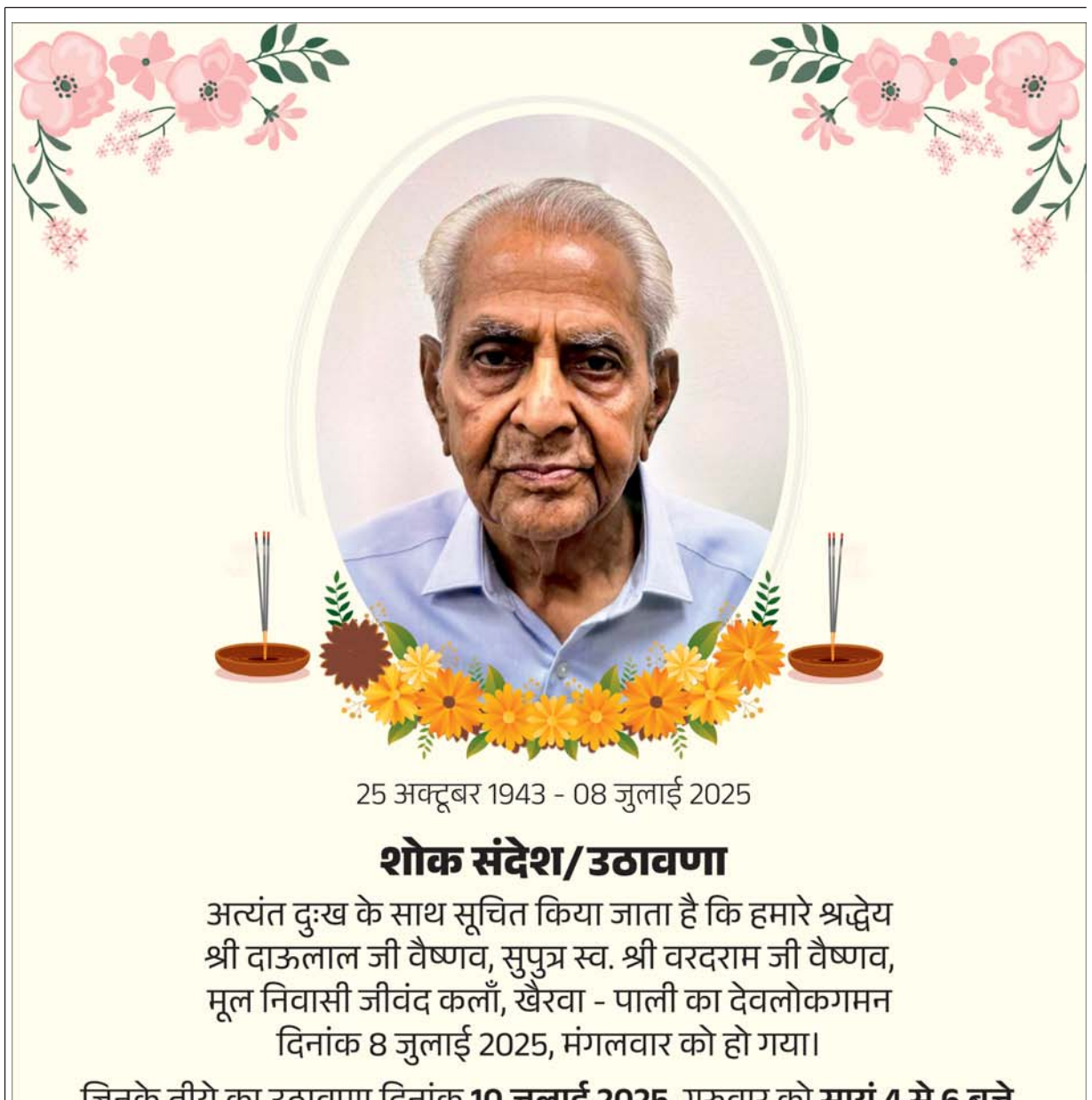

25 अक्टूबर 1943 - 08 जुलाई 2025

शोक संदेश/उठावणा

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे श्रद्धेय
श्री दाऊलाल जी वैष्णव, सुपुत्र स्व. श्री वरदराम जी वैष्णव,
मूल निवासी जीवंद कलाँ, खैरवा - पाली का देवलोकगमन
दिनांक 8 जुलाई 2025, मंगलवार को हो गया।

जिनके तीये का उठावणा दिनांक **10 जुलाई 2025,** गुरुवार को **सायं 4 से 6 बजे,**
महावीर कॉम्प्लेक्स, तार घर के पास, सरदारपुरा, जोधपुर में रखा गया है।

शोकाकुल

धर्मपत्नी : श्रीमती सरस्वती देवी

पुत्र-पुत्रवधू : अश्विनी वैष्णव-श्रीमती सुनिता
आनन्द वैष्णव-श्रीमती ऊषा

पुत्री-जंवाई : आरती-चिरंजिवी जी, वंदना-गौरव जी

पौत्र-पौत्री : श्रेयांश, राहुल, तान्या, दिव्यान्श

दोहिता-वधू : कार्तिक-तबिशी, कृतिका, प्रज्ञा, अभ्युदय

ससुराल पक्ष: उम्मेदराम जी, श्रवणदास जी-सोनिया, रूपचंद जी-सरस्वती
भंवरदास जी-सुखी, किरणदास जी-इन्द्रा, प्रमोद जी-पिन्टू

निवास : C-17, महावीर कॉलोनी, शिवम अस्पताल के पास, रातानाडा, जोधपुर
मो. 9829934545, 9166991308

सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा इंडिया ब्लॉक

राष्ट्रव्यापी हड़ताल में विपक्षी दलों की एकजुटता व तालमेल दिखाई दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जुलाई। बुधवार को पूरे भारत में उस समय असंतोष की लहर दौड़ गई जब ट्रेड यूनियनों, मज़दूर संगठनों और विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार की विवादित मज़दूर नीतियों और बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ समन्वित रूप से देशव्यापी प्रदर्शन किए। इन विरोध प्रदर्शनों का चरम बिंदु "बिहार बंद" था, जिसे सफल माना गया है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक टकराव को नई ऊर्जा दे दी है।

बिहार से उठी इस आवाज़ की गूंज देश के अन्य हिस्सों में भी सुनाई दी। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में - जो मज़दूर आंदोलनों और वामपंथी सरकारों के लिए जाने जाते हैं - बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में जनसभाएं, रैलियां और सार्वजनिक परिवहन में बाधाएं इस व्यापक मजदूर-असंतोष का प्रतीक बनीं। हड़ताल को आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, सीआईटीयू तथा एआईयूटीसी जैसी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला, जिन्होंने सरकार की नीतियों को "मज़दूर-विरोधी और जन-विरोधी" करार दिया तथा मजदूर-संरक्षण को कमजोर करने वाला बताया।

- प.बंगाल में लम्बे अर्से बाद वामपंथी दलों की सक्रियता देखी गई। केरल में भी वामपंथी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
- नई दिल्ली में जंतर-मंतर दिन भर विरोध प्रदर्शनों का केन्द्र बना रहा।
- राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चरम बिंदू दिखा बिहार बंद में।

दिल्ली में राजनैतिक कार्यवाहियों का हृदय माना जाने वाला 'जन्तर मंतर' दिन भर प्रतिरोध का केन्द्र बना रहा, क्योंकि देशभर से आए मज़दूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ दिन भर धरना - प्रदर्शन किया। वरिष्ठ यूनियन नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार द्वारा लायी जा रहीं चार नई श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) की निंदा की। एक एआईटीयूसी नेता ने "ये कानून मज़दूरों के वर्षों की लड़ाई से हासिल अधिकारों को छीनकर कंपनियों को निरंकुश शक्तियाँ देते हैं।" बैनर, नारे और जोशीले भाषणों के बीच, प्रदर्शनकारियों ने इन श्रम संहिताओं को वापस लेने और मतदाता सूची में छेड़छाड़ बंद करने की मांग की। मज़दूर असंतोष और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर उठे सवालों ने मिलकर एक तीव्र राजनीतिक माहौल बना दिया है। जो विरोध केवल श्रम कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, वह अब लोकतंत्र, पारदर्शिता और आर्थिक न्याय जैसे व्यापक मुद्दों पर आधारित एकजुट प्रतिरोध आंदोलन में बदलता जा रहा है। जैसे-जैसे इंडिया गठबंधन सड़कों पर सक्रियता दिखा रहा है और जनता को संगठित कर रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आंदोलन भविष्य में एक ठोस चुनावी चुनौती में तब्दील हो सकता है। परंतु फिलहाल, बुधवार का 'बिहार बंद' एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरा है - जो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908